PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SIXTY-SECOND AND SIXTY-FOURTH REPORTS

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee:—

(i) Sixty-second Report (Seventh Lok Sabha) on Action taken by Government on the recommendations contained in Hundred and Thirty-eighth Report of the Committee (Sixth Lok Sabha) on Delhi Development Authority.

(ii) Sixty-fourth Report (Seventh Lok Sabha) on paragraphs 6 and 14 of the Report of Comptroller and Auditor General of India for the year 1979-80, Union Government (P. & T.) relating to Arrears of Telephone Revenue and Expansion of Srinagar Telephone Exchange.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

TWENTY-FIFTH REPORT & MINUTES

SHRI BANSI LAL (Bhiwani): I beg to lay on the Table the Twenty-fifth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings on Delhi Transport Corporation—Accidents and Operation of Private Buses and Minutes of the sittings of the Committee relating thereto.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DEATH OF SEVERAL PERSONS DUE TO COLD WAVE

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"देश में शीत लहर के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के समाचार।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय का कृषि मंत्री से क्या सम्बन्ध है ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इसका कृषि मंत्री से कोई संबन्ध नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने इस विषय को महत्वपूर्ण माना। आप इसको सदन में लाए। जवाब देंगे कृषि मंत्री ! इसका उत्तर देना चाहिए प्रधान मंत्री को।

अध्यक्ष महोदय : यह उनको एलाट है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या केवल खानापूरी करनी है ? आप सहानुभूति प्रकट करते हैं मरने वालों के साथ। कृषि मंत्री क्या उत्तर देंगे, आप मुझे बताइए।

अध्यक्ष महोदय : यह उन्हीं को एलाट है। मैं क्या करूं ? यह चार्ज उन्हीं का है। मैं किसको कहूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोग सर्दी से मर रहे हैं। क्या इसका इन्तज़ाम कृषि मंत्री करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जिसको जो सबजेक्ट एलाट है, वही उसका जवाब देगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्लानिंग किस लिए है ?

अध्यक्ष महोदय : आप रास्ता बताइए। जिसको एलाट है, वही जवाब देगा। प्लानिंग कमीशन को कैसे कहूँ ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जवाब सुन लीजिए। आपने यह कालिंग एटेन्शन नोटिस जिस इरादे से एडमिट किया था, वह सारा इरादा विफल हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बताइए कि मैं क्या करूं। I can only ask the Minister Incharge. Whom should I ask ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You ask the Prime Minister.

श्री मनीराम बागड़ी : कृषि मंत्री हैं क्या ? कौन हैं कृषि मंत्री ? यह हैं कृषि मंत्री ? प्रधान मंत्री से आए कृषि मंत्री पर और कृषि मंत्री से साढ़े-चार-फुटे तक आ गए। क्या मज़ाक किया है मरने वालों पर ? और इस बयान को पढ़ना !

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): According to the PTI report, there has been a death toll of 39 human being in Bihar, due to cold wave.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अगर हिन्दी जानते हों, तो हिन्दी में पढ़ दें।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शीत लहर के कारण 39 आदमियों की मृत्यु हुई है। मैं इन व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। तथापि, भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कृषि मंत्रालय ने उत्तरी क्षेत्र की राज्य सरकारों को पहले ही टेलेक्स भेज कर उनसे अनुरोध किया है कि वे इस शिशिर ऋतु के दौरान शीत लहर से हुई मौतों, मृतकों के निकट सम्बन्धियों को दी गई वित्तीय सहायता तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपचारात्मक उपायों के बारे में तुरन्त रिपोर्ट भेजें। हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भागों में 10 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 1981 के बीच शीत लहर की स्थिति थी।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारें आम तौर पर ऐसी आपदाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति मुख्य मंत्री राहत निधि या राज्य सरकार की स्वेच्छा निधियों से करती हैं। कभी कभी राज्य सरकारें और अन्य स्वेच्छिक संगठन प्रारम्भिक उपाय करते हैं, जैसे कम्बलों और कपड़ों का वितरण करना। मृत व्यक्तियों की पहचान होने पर उनके सगे सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की

मंजूरी की जाती है। कुछ राज्यों में जन प्राधिकरणों के पास रैन बसेरा जैसी व्यवस्था भी होती है जहां बेपनाह लोगों को शीत लहर से बचाने के लिए पनाह दी जाती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब सुन लिया ? कृषि मंत्री फसल देखते हैं या इंसानों की भी चिन्ता कृषि मंत्रालय को सौंप दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : जो उनको दिया गया है वह दिया गया है, अब उसमें आप क्या करेंगे ?

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, मैं कोई सख्त और असभ्य शब्द नहीं कहता हूँ, लेकिन हमेशा जब गरीब की मांग उठती हैं तो अभागे गरीब लोगों के लिए अभागे देश के अन्दर ऐसा ही जवाब मिलता है। इसके अन्दर पी० टी० आई० की एक रपट की बात की गई है जिसमें मरने वालों की संख्या 35 बतायी गई है। मैं रपट लाया हूं, यहां जो इनकी लाइब्रेरी है वहां से, क्यों कि मेरे पास कोई सरकारी मशीनरी नहीं है, उसमें उन्होंने यू० पी० के गढ़वाल क्षेत्र की मृत्यु भी बताई है और देश के अन्य भागों में हुई मृत्यु भी बताई है। उनकी रपट के मुताबिक जो अखबारों के आधार पर है, 45 की मृत्यु बताई गई है। ये यहां पर पी० टी० आई० की रपट दे रहे हैं कि उसके मुताबिक इतनी मौत हुई हैं जैसे कोई विदेशी बी० बी० सी० बोल रहा हो लन्दन से और इस सरकार से उसका कोई सम्बन्ध न हो। ये पी० टी० आई० की रपट पर बयान देंगे या शासन का कोई बयान देंगे ? अगर वह ऐसा बयान देंगे तो आप उसको सरकारी बयान मानेंगे या क्या मानेंगे ? पहली बात तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं। फिर मैं सवाल करूंगा। कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया है सरकार के बिहाफ पर उसके बारे में मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी बयान दिया है या पी० टी० आई० का बयान दिया है ? इन्होंने राज्य सरकारों से कोई जानकारी की या नहीं की ? उन से इनको कोई जानकारी मिली या नहीं ? अगर मिली तो क्या मिली और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली ? इन्होंने उनसे जानकारी क्यों नहीं ली ? यह जरा इनसे पूछिए कि यह सरकारी बयान है या गैर-सरकारी ?

अध्यक्ष महोदय : आप यही सवाल पूछ लें। उसमें ही आ जायगा। अपने आप जवाब देंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी आपकी फराखदिली मानता हूँ कि आप ने गांधी की लिंगोटी को फिर एक दफा दोबारा इस सवाल को उठाने का मौका दे कर महत्व दिया है। गुलाम देश में एक बार गांधी जी लिंगोटी पहन कर विलायत गए थे। उन लिंगोटी पहनने वाले लोगों के सवाल को फिर इस सदन में चाहे हलके ढंग से ही वह उठा, लेकिन उस लिंगोटी के सवाल को फिर इस देश में उठाने का मौका आप ने दिया है। इसी सदन में एक दफा डा० राम मनोहर लोहिया ने तीन आने और पन्द्रह आने का सवाल छेड़ करके हिन्दुस्तान के कोटि-कोटि उन लोगों का सवाल उठाया था जो भूख से पीड़ित हो कर या तो मर जाते हैं या मौत के करीब पहुँच जाते हैं या आधी जिन्दगी पर मरते हैं, उन लोगों का सवाल उठा कर उन्होंने देश को झकोरा था। आज फिर वैसा ही सवाल, उसी किस्म का सवाल इस सदन में उठने का मौका आया है।

[श्री मनीराम बागड़ी]

यह सत्य बात है कि कृषि मंत्री जी के बस का यह सवाल नहीं है और यह इनके बस का सवाल तो कत्तई नहीं है। इस से कुछ निकलेगा या शासन कुछ निकालेगा यह भी उम्मीद नहीं है। लेकिन कम से कम यतीम या जिसका कोई वारिस नहीं है, लावारिस की मौत पर अगर कोई जनाजा उठाने वाला भी आ जाय तो भी बेहतर है। मैं यही समझूंगा कि हिन्दुस्तान के एक नहीं, दो नहीं, बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनका सवाल तो उठा। दुनिया की आबादी का 1/5 हिस्सा आबादी जो हिन्दुस्तान है और उसमें दुनिया की 50 प्रतिशत दरिद्रता का जो घर है, दुनिया में 40 प्रतिशत अपच्यता का और दुनिया के 40 प्रतिशत बीमारों का जो घर है उसमें जो इस तरीके से मरने वाले हैं उनकी तरफ कुछ ध्यान तो जाय। यह ठीक है कि रेल दुर्घटना, कुतुबमीनार की घटना, बस से मरने की घटना, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उसमें सरकारी मशीनरी या सरकार की छोटी मोटी गलती होती है और इस तरह की दुर्घटना अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, सभ्य से सभ्य और असभ्य से असभ्य देशों में भी हो सकती हैं। लेकिन जिस देश के अन्दर भूख से कोई मरेगा, सर्दी से कोई मरेगा, शीत लहर से कोई मरेगा, उसकी सीधी जिम्मेदारी शासन न ले तो समाज जरूर लेगा और समाज न ले तो मुझ जैसा छोटे आदमी को तो उस जिम्मेदारी को लेने में कोई परहेज और गुरेज नहीं है। गांधी जी इस देश के महान व्यक्ति थे। लिंगोटी क्यों पहनते थे? उनको भी कोट पतलून वगैरह सब कुछ मिल सकता था। आप जरा देश की व्यवस्था को समझिए। सिर्फ 35 मौत बतलायी हैं और ये जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 45 हैं। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र की मौत का हवाला उससे पहले है। शासन ने, न तो प्रान्तीय शासन ने यह जिम्मेदारी समझी कि केन्द्र को पता दे और न केन्द्र सरकार ने जिम्मेदारी अपनी महसूस की कि अगर प्रान्तों में इस तरह की मौत हो रही हैं, इस तरीके से इन्सान मर रहे हैं तो उनके आंकड़े इकट्ठे किए जायें और क्यों मर रहे हैं इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि राज शक्ति और शासन सिर्फ व्यक्ति, परिवार या चन्द व्यक्तियों या दिल्ली के इस कनाट प्लेस या लाख दो लाख ऐसे घरानों के आगे उन दुःखी और गरीब लोगों की मौत की तरफ नहीं देखती है। मोटे-मोटे शब्दों में मैं इसका कारण बता दूं। हिन्दुस्तान में अगर छोटा सा काम भी हो जाता, अगर अरबपतियों को भी खत्म कर दिया जाता या अगर ऐसा भी कर देते कि एक करोड़ से ज्यादा किसी के पास सम्पत्ति नहीं रहेगी तो भी कोई बात थी। लेकिन यहां पर जब यह सवाल उठता है तो कहते हैं क्या गरीबी बांट लें। गरीबी बांट लो तब भी अच्छा है। लेकिन गरीबी तो बटने वाली नहीं है, अमीरी ही बांट लो। एक करोड़ की बात भी करोगे तो 500-700 आदमियों से कुछ आयेगा।

अध्यक्ष जी, आप बुरा मत मानियेगा, पाप का समुन्दर बहता है तो उसमें जो स्वार्थी होते हैं, बढ़ाई करने वाले होते हैं, भाट जहां पर ज्यादा होते हैं, वहां पर बढ़ाई की इच्छा ज्यादा होती है वहां एक दो त्यागी पुरुष समुन्दर में चल नहीं सकते हैं। आप भी बह गए हैं, मैं भी बह गया हूं और दूसरे लोग भी बह गए हैं। ढ़ाई हजार करोड़ जिस देश में खेल तमाशे पर लगाया जा सकता है, अगर यहां का हर मन्त्री इस किस्म की भावना को लेकर चलें, **

** Expunged as ordered by the Chair.

'आपको कोई पार्ट देंगे किसी जाट का या सरदार का और उस पर भी लाखों करोड़ों खर्च करेंगे और उधर कम्बल के बिना आदमी मरेंगे। किरण बेदी बेचारी कहीं नौकरी करती है यहां पर, तो यह साठे उसको नौकरी नहीं करने देगा, गुजराती का पार्ट कराके दिखायेगा यहां पर, और उसको फैंसी ड्रेस बतायेगा। (व्यवधान) आज एक खरब और कितने अरब का कर्जा इस देश पर है—वह कर्जा मरने वालों से कैसे वसूल किया जायेगा ? कम से कम तीन सौ और चार सौ के बीच प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा है।

हिन्दुस्तान में शीत लहर से लोग मरते हैं लेकिन दुनिया में ऐसे भी सर्द मुल्क हैं जोकि बर्फ से ढके रहते हैं वहां पर लोग क्यों नहीं मरते हैं ? फिर, यह जो आंकड़े दिए गए हैं वह भी गलत हैं। समूचे भारत में हर साल एक लाख से कम लोग शीत लहर से और एक लाख से कम लोग गर्म लहर से नहीं मरते। ये लोग मरते हैं झुग्गियों में और स्टेशन्स पर, यहां कनाट प्लेस में या इन शाही महलों में नहीं मरते हैं।

फिर आप शीत लहर की मौत किस को मानते हैं ? बिहार में अगर चार बच्चे सर्दी से अपनी जिन्दगी बचाने के लिए कोयले का धुआं करते हैं और उसमें कहीं उनकी आंख लग गई जिससे वे चारों मर गए तो वह कौन सी मौत हुई ? आप कहेंगे कि वे शीत से नहीं मरे, गैस से मर गए। आप कहेंगे कि शीत से नहीं मरे, निमोनिया से मर गए या कहेंगे शीत से नहीं मरे, हार्ट अटैक से मर गए। शीत लहर से मौत का तो एक ही मतलब है कि इन्सान के पास सर्दी से अपनी जिन्दगी को बचाने का साधन न होना। इसमें कृषि की भी थोड़ी-बहुत जिम्मेदारी आती है। इसलिए आती है कि कपड़े के बिना मरते हैं। आज इस देश में साल में सिर्फ दस गज पर-कैपिटा कपड़ा है। कुछ ऐसे घर हैं जो शराबी हैं या कहीं पाउडर और लिपिस्टिक लगाने वाली घर वाली है वहां कपड़े का सारा बजट शराब ही ले जाती है। कपड़ा विदेशों को भेजा जाता है, जिसकी वजह से इतनी कमी है कि .85 मीटर फी-महीने फी-कस की एवरेज आती है, जिस में एक ब्लाउज भी नहीं बन सकता है। अगर उन लोगों को लिया जाय जो गरीबी की सतह के नीचे हैं तो वही लोहिया जी की 3 आने और 15 आने वाली बात आ जाती है—उनके पास तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है। दूसरी तरफ आप और हम में से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास 50-50 ड्रेसें हैं, 50-50 रजाइयां हैं। जो अरबपति है उन का तो हिसाब ही कुछ नहीं है, सारा कपड़ा शहरों में निकल जाता है गांवों तक पहुंचने के लिए बच ही नहीं पाता। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी इलाके इस बात के प्रमाण हैं कि वहां के नर और नारियों को तन ढकने के लिए कुछ नहीं मिल पाता है। तन ढकने के लिए जो "चिंदी" मिलती उससे तन ढकना तो दूर, वहां की नारिया छाती तक नहीं ढक पाती हैं। जब वह सर्दी से मर जाते हैं तो कहा जाता है निमोनिया से मर गये, हार्ट-एटेक का नाम लेते हैं, दूसरे किसी रोग का नाम लिया जाता है। सर्दी का असर किस पर पड़ेगा ? जो अच्छा खाना खायेगा, शराब पीयेगा, टोस्ट और अण्डे खा कर जायगा, उसको सर्दी नहीं लगती है। सर्दी किसको लगती है—जैसे एक खेत में पानी का बांध टूट गया, पानी बन्द नहीं हो रहा

[श्री मनीराम बागड़ी]

है, बहन और भाई—दोनों उसको बन्द करने जाते हैं, भाई उसको लेट कर रोकना चाहता है, बहन मना करती है, लेकिन भाई उस बांध के आगे लेट जाता है, बहन "कस्सी" से मिट्टी डालती है और जब उसकी मौत हो जाती है तो कहा जाता है कि भूख के कारण मौत हो गई है। ···(**व्यवधान**)··· शायद कुछ मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी बैठे हुए हैं ?

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ऐसा लगता है कि ज्ञान का ठेका आपने ही ले रखा है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं समझता था कि मैं ही मूर्ख हूं, लेकिन आप तो मुझ से भी ज्यादा मूर्ख निकले।

यह किसी एक व्यक्ति या पार्टी का सवाल नहीं है। यह सही है कि जितनी सरकारें आज तक यहां आईं, कोई भी सरकार इस सवाल को हल नहीं कर सकी है और जब तक इस सवाल को हल नहीं किया जायगा, तब तक कोई भी सरकार नहीं टिकेगी और टिकनी भी नहीं चाहिये। अगर जबरदस्ती टिकेगी तो फिर सिविल-वार होगी, बगावत होगी, कत्लेआम होगा, बहुत दिनों तक इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

मैं गांधी जी के शब्दों की तरफ आप को ले जाना चाहता हूं—चव्हाण साहब को टोपी बहुत प्यारी है, इस लिये उनसे ज्यादा कहता हूं, क्योंकि टोपी के कारण वे इधर से उधर चले गये। गांधी जी ने लिखा है—कांग्रेस वालो, संभल जाओ, एक ज़माना वह आयेगा, जब जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं करोगे और जनता भूखी मरेगी, तो वह दिन दूर नहीं जब जनता एक-एक धौली टोपी वालों को चुन-चुन कर मारेगी···· (**व्यवधान**)··· बगैर टोपी वालो, मेरी शरण में आ जाना, मैंने पहले भी बहुत कुटते हुओं को बचाया है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है, वह मुकम्मिल जवाब नहीं है, इन के पास कोई जवाब है भी नहीं, ये बेचारे जवाब नहीं दे सकते। मुझे इन पर गुस्सा नहीं, बल्कि दया आती है। इनका तरीका क्या है ? इनकी अगर सरकारी मशीनरी होती — एक हजार आदमियों पर चिकित्सा की व्यवस्था होती, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, और गांव-गांव वे जाते, तो कुछ हो सकता था लेकिन जो आपका बी०डी०ओ० बैठा हुआ है और जो दूसरे लोग हैं वे मंत्रियों के उद्घाटन और दुर्घाटन का कार्य करते रहते हैं। वे यदि इन कामों में लगे रहते इन कामों से जुड़े होते, तो कहीं कुछ हो सकता था। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप कम से कम इस विषय पर पूरी बहस करवाइए, इस पर चर्चा चलवाइए, तब इस बारे में कुछ होगा। मैं मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि आप ने शासन से कोई इत्तिला ली या नहीं और दूसरा यह है कि जो गलत आंकड़े आपने पेश किये हैं, उस के लिए आप सदन से क्षमा याचना करें। मेरे पास पी०टी०आई० के आंकड़े हैं, जो आप से अलग हैं। आप कहें, तो मैं उन को सदन के पटल पर रख सकता हूँ। इसलिए इस अधूरे सवाल पर मैं बोलूं, कुछ जमता नहीं है, कुछ सजता नहीं है। खेलों पर आपने इतना पैसा खर्च कर दिया और अध्यक्ष जी, मैं आप से अपील करूंगा कि प्रधान मंत्री जी जो हैं, वे साठे साहब के चंगुल में फंस कर कहां जाएंगी, जो उन के दरबारी बनते हैं।

वे कोई** को ले आएंगे और फिर उन पर मुकदमा बनेगा। इस में कोई फायदा नहीं है, यह देश का पैसा फजूल जा रहा है। यह जो प्रदर्शनी में पैसा लग रहा है, यह पैसा फजूल जा रहा है। (व्यवधान) ...

श्री बालेश्वर राम : अध्यक्ष जी, मनीराम बागड़ी जी यहां के बहुत पुराने सदस्य हैं और गांधी जी की दुहाई देकर उन्होंने अपने भाषण को शुरू किया और काफी लम्बा भाषण उन्होंने दिया। कितना तर्कसंगत उनका भाषण है, उस में मैं नहीं जाना चाहता, वे तो मिनटों में खड़े होकर व्यवधान करने की कोशिश करने लगते हैं। इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता और मैंने अपने जवाब में कहा है कि इस तरह की जो मौतें हुई हैं, वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं और मानवीय दृष्टिकोण से इस में किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जहां उन्होंने महात्मा गांधी जी की दुहाई देते हुए अपना भाषण शुरू किया, वहां कुछ राजनीतिक बातें भी उन्होंने अपने दिमाग में रखीं और फिर शासन की बात कही और दूसरी सारी बातें कहीं, जो इस की परिधि में नहीं आतीं। उनका** सभी याद आते हैं।

सवाल यह है कि इस कालिंग एटेंशन को आप ने स्वीकृत किया और आप का आदेश मिलते ही हम लोगों ने इसकी छानबीन करने की कोशिश की, पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और कल ही हमारे विभाग के जो उच्चाधिकारी थे, उन्होंने टेलेक्स तो भेजा ही लेकिन उस के साथ टेलीफोन से भी सम्पर्क स्थापित करना शुरू किया। आम तौर से यह जो पी० टी० आई० की न्यूज है, उसमें बिहार का ही जिक्र था। बिहार में कल तक की फीगर 35 थी, 35 लोगों के मरने की रिपोर्ट थी लेकिन आज खुद ही मैंने देखा कि 39 की रिपोर्ट अखबारों में है और खास तौर से बिहार के बारे में वह रिपोर्ट थी। इसलिए बिहार के चीफ सेक्रेटरी से सम्पर्क स्थापित किया गया। आप जानते हैं कि वहां अभी भी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। इस वजह से कहां-कहां मौतें हुई हैं, यह आइडेंटीफाई होना इस वक्त संभव नहीं था। जितनी भी मौतें हुई हैं, मैंने शुरू में ही कहा और किसी की भावना इससे अलग नहीं हो सकती कि इसमें गरीब मरते हैं और आम तौर से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर नहीं हैं, जो भीखमंगे हैं और बेघर हैं। उनकी मौतें ही ऐसे हो जाती हैं जब काफी ठंडी लहरें चलती हैं, जब कोल्ड वेव चलती हैं। इस से हम इन्कार नहीं कर सकते लेकिन फिर भी जो अखबारों के माध्यम से हमें सूचना मिली थी, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स से आइडेंटीफाई करना उन के लिए संभव नहीं था क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है, वहां पर कर्मचारी इस वक्त भी हड़ताल पर हैं। फिर भी और भी जो राज्य सरकारें हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारें हैं, उनसे भी सम्पर्क स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे यहां इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों के बारे में भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बारे में जो रिपोर्ट मिली है, जहां बहुत सी मौतें हुई लेकिन यह एक-दो जगह की बात नहीं है, एक स्थान पर कहीं होता, तो उसकी सूचना आसानी से मिल सकती थी लेकिन कई जगहों की रिपोर्टें आप सब ने देखी होंगी। अखबार की रिपोर्ट में यही हैं कि कहीं मोकामा में, कहीं बेगूसराय में और कहीं नवादा में ऐसी मौतें हुई हैं।

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री बालेश्वर राम]

इस सब जगहों के बारे में हम सूचना एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा इन्होंने कहा है और यह सही बात है कि जो ग़रीब है, वही इस में मरता है। अपने भाषण में इन्होंने कई सरकारों की चर्चा की है। कोई भी यह दावा नहीं करता है कि हमने पूरी तरह से ग़रीबी का उन्मूलन कर दिया है, पूरी तरह से लोगों को कपड़े मिल गए हैं, मकानात मिल गए हैं हम यह कभी दावा नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ज़रूर है और हम चाहते हैं कि यह सब मुहैया हों। हाउसिंग प्राब्लम के बारे में हाउसिंग डिपार्टमेंट ज्यादा ब्यौरेवार जवाब दे सकता है। वैसे कुछ हाउसिंग स्कीम्स रूरल एरियाज़ में, अरबन एरियाज़ में स्लम क्लीयरेंस की स्कीम्स शुरू की गई हैं और कुछ जगहों पर शेल्टर्स भी दिए गए हैं। दिल्ली में भी आप देखेंगे कि जो डिस्प्यूट्स हैं, बैगर्स हैं, जिनके पास घर नहीं हैं, उनके लिए रैन-बसेरा स्कीम शुरू की गई है। अन्य जगहों पर भी स्थानीय संस्थाओं से, म्युनिस-पेलिटीज़ से, कारपोरेशंस से कहा गया है कि वे इस तरह के काम करें और जिनके पास शेल्टर नहीं हैं, उनको मिलने चाहिएं।

यह सवाल पहले पहल सामने आया है। इसके लिए उत्तर में बताया है कि इस तरह की मौतों को आइडिएंटीफाई किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों के पास जो साधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग होना चाहिए। अभी तक तो इस तरह का उपबंध भारत सरकार के कोष में नहीं था। इस लिए .....।

श्री मनीराम बागड़ी : इसका मतलब है कि भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पहली दफा महसूस की है ?

श्री बालेश्वर राम : महसूस तो पहले से करती है और प्लानिंग में जो पैसा देते हैं, उसमें आने वाली विपत्तियों को और प्राकृतिक विपदाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत सरकार भी इसके लिए धन देती है, लेकिन शासन चलाने का काम राज्य सरकारों का है। हमने उनको निर्देश दे दिए हैं कि उनके पास जो फण्ड्स हैं, उनका उपयोग करें।

बागड़ी जी ने जो सूचनाएं दी हैं, इसके अलावा भी जो सूचनाएं उनके पास हैं, वे हमको दे दें, हम उनकी जांच करवाएंगे। उन्होंने जो सूचना दी है वह भी किसी आधार पर दी होगी, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि उनकी सूचना गलत है। हम इसकी जांच करेंगे। हमारे पास सरकारी माध्यम से पूरी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, फिर भी मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि उनके पास जो साधन हैं, उनसे प्रभावित लोगों की मदद करें। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सचेष्ट होने की आवश्यकता है।

श्री मनीराम बागड़ी : लखनऊ की पी० टी० आई० की खबर है कि गढ़वाल में मौतें हुई हैं।

श्री बालेश्वर राम : मैंने कहा है कि आप पूरी सूचनाएं दे दीजिए। सरकार के पास अभी पूरी सूचनाएं नहीं आ पाई हैं। हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Are you satisfied with this ?

MR. SPEAKER: We have to be more careful ; we have to address ourselves.

हमें ध्यान करना पड़ेगा और प्रांतीय सरकारों को सचेष्ट और सचेत करना पड़ेगा कि वे मसले पर ध्यान दें कि सर्दियों में ऐसा होता है, इस पर विशेष ध्यान दें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मसला होगा, जिससे अटेन्शन आ जाएगी और फायदा होगा। इससे लोग सजग हो जाएंगे। यह मानवीयता की पुकार है, इस तरीके से इस को लेना चाहिए।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : ठीक है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी कितनी उपेक्षा की जा रही है, यह इसी से साफ जाहिर होता है कि जहां इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, उन्होंने कृषि मंत्री को कह दिया और वे मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने जूनियर मिनिस्टर को कह दिया।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

12.33 hrs.

इससे लगता है कि सरकार इस मामले को गम्भीरता पूर्वक नहीं ले रही है। अभी कोई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ जाए तो....।

MR. DEPUTY SPEAKER : I think you are not a junior Member in your party.

SHRI HARIKESH BAHADUR: I may be a junior Member. But the Ministers should be senior Ministers because the issue raised is an important one.

SHRI MANI RAM BAGRI: Here is Deputy Speaker in the Chair. The Hon. Member is Deputy Leader of his party, and the Minister is Deputy Minister. All are 'Deputies'.

श्री हरिकेश बहादुर : हालांकि माननीय मंत्री जी को गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि ये अपने को प्रधानमन्त्री से कम नहीं समझते।

श्री बालेश्वर राम . नहीं कोई गुस्सा नहीं आ रहा।

श्री हरिकेश बहादुर : इन्होंने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि जब अध्यक्ष जी आप ने जब एडमिट कर लिया तब इसकी जानकारी एकत्र करना शुरू की गई। पहले से यह कोई जानकारी नहीं ले रहे थे। इतना निकम्मा यह विभाग है, इसकी निंदा की जानी चाहिए कि इसने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी जब तक अध्यक्ष जी ने निर्देश नहीं दिया कि सदन में यह मामला आ रहा है और आपको जवाब देना है। इसके पहले किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं समझी गई। यह बात अभी वक्तव्य में कही गई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का वक्तव्य इतना गैर-जिम्मेदाराना है और इस पर मैं गहरी आपत्ति करता हूं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार इस गम्भीर मामले में कोई रुचि नहीं ले रही है। जो सूचना मन्त्री महोदय ने दी है वह बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। पी० टी० आई० की खबरों के आधार पर जवाब दे दिया गया है। हमें मालूम है कि देश के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है। कुछ ही भागों में हुई मौतों के आधार पर इन्होंने यह खबर दे दी है। सैंकड़ों लोगों की मौतें इस शीत के कारण हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब मन्त्री महोदय को सही

[श्री हरिकेश बहादुर]

खबर मिलेगी तो क्या वह उसकी जानकारी सदन को देंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति है। इनके पास अभी तक राज्यों से जबाब नहीं आया है, यह इन्होंने कहा है। मैं समझता हूं कि जब से ये मन्त्री आए हैं, यह सरकार आई है, यह बिल्कुल निकम्मी सरकार है। गरीब लोग ही मुख्य रूप से इस प्रकार की आपदाओं से प्रभावित होते हैं, चाहे आर्थिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, महामारी का संकट हो, सब प्रकार की दैवी विपत्तियों का शिकार यही लोग होते हैं। जो गरीबी में जीवन बिताते हैं वही इनका शिकार होते हैं। यह घटना इस साल ही नहीं हुई है। हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं। सरकार का ध्यान शायद इस वक्त ही इस ओर गया है। इससे पहले इसकी ओर जाने का सवाल ही पैदा उसके लिए नहीं हुआ था। एशियन गेम्ज जो हो रही हैं उनपर एक हजार करोड़ से भी अधिक खर्च ये करने जा रहे हैं····

आचार्य भगवान देव : इस सवाल से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री हरिकेश बहादुर : न्यूयार्क की सड़कों पर नंगे नाच करने से इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। यह एक गम्भीर सवाल है। जो लोग अमरीका और न्यूयार्क में रंग-रेलियां मनाते हैं उनको इससे क्या मतलब कि इस देश में क्या हो रहा है ··· **(व्यवधान)** इनको मेरी बात बुरी क्यों लग रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

एक हजार करोड़ रुपया पानी की तरह एशियन गेम्ज में बहाया जा रहा है लेकिन जो लोग शीत लहर से मर रहे हैं, जिन के खाने की, कपड़े की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। कई बार इस प्रश्न को सदन के अन्दर और बाहर भी उठाया गया हैं। यहां पर इस की चर्चा हुई है। क्यों धन का दुरुपयोग किया जा रहा है यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। लेकिन धन का दुरुपयोग किया जाएगा, धन को बरबाद किया जाएगा गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए, अमीरों की सुख सुविधा और उसके भोग विलास के लिए। गरीबों की रक्षा के लिए धन इस्तेमाल नहीं होगा। यह इस सरकार की नीति है।

यह सही है कि स्वयं सेवी संस्थाओं, समाज के दूसरे लोगों, पूरे समाज का यह उत्तरदायित्व है कि इस प्रकार से पीड़ा में फंसे हुए लोगों के कष्टों को दूर किया जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन सरकार का उत्तरदायित्व सब से अधिक है क्योंकि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि लोगों के जीवन की रक्षा वह करे। गोरखपुर जिले में बाढ़ आई थी और उस कारण तमाम गांव पूरे तरीके से बरबाद हो गए थे, लोगों के मकान गिर गए थे। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनको मकान बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी। लेकिन आज गोरखपुर में भी शीत से मौतें हो रही हैं। लोगों के पास घर नहीं हैं। शीत में खुले में वे जीवन बिता रहे हैं। तमाम तरह की कठिनाइयां उनको उठानी पड़ रही हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितनी धनराशि उन्हें देने का आश्वासन दिया गया था उतनी नहीं मिल सकती है। जो कुछ थोड़ी बहुत मिलनी चाहिये वह भी नहीं मिल रही है। वहां लोग तरह-तरह के कष्टों और परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। इस चीज को हम लोगों ने देखा है और देख रहे हैं। सरकार उनके वास्ते

आवास की, मकानों की व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिन लोगों के मकान पूरे तरीके से गिर गए हैं उनको मकान बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब उनको यदि आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी तो वे भी उसी प्रकार से मौत के शिकार होंगे जिस प्रकार से देश के अन्य भागों में लोग हो रहे हैं। इसके बारे में कृषि मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा और राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार मदद देगी। लेकिन उनकी मदद नहीं हो रही है। गोरखपुर जिले में लोग शीत से मर रहे हैं। इनके विपरीत धन का दुरुपयोग एशियन गेम्ज वगैरह में तथा दूसरी तरह के कार्यकलापों में किया जा रहा है। इस दुरुपयोग को रोक कर ऐसे लोग जो गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, कपड़े, खाने और मकान की व्यवस्था न होने के कारण मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, क्या उनकी मदद की जाएगी ? क्या ऐसे लोगों के लिये आवास, भोजन और कपड़े की व्यवस्था की जायेगी ? सरकार की इसके बारे में क्या स्पष्ट नीति है मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री बालेश्वर राम : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। सबसे पहले तो इन्होंने पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के बारे में उन्होंने कहा कि मंत्री को क्या जवाब देना चाहिये। पिछली दफा जब चुनाव हुए तो हमारे टिकट पर यहां से चुन कर गए और उधर चले गये.....

श्री हरिकेश बहादुर : इन्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते। यह मजाक करते हैं.....

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY SPEAKER: Don't record. I am not allowing anybody else. Nothing will go on record. Only Minister's reply will go on record.

श्री बालेश्वर राम : यहां तो सभी मेम्बर बराबर हैं.....

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY SPEAKER : Don't record anything.

श्री बालेश्वर राम : मेरा भी 30 वर्ष का पार्लियामेंटरी एक्सपीरियेंस है। यह पैदा नहीं हुए होंगे। क्या बात कर रहे हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Please answer to the points only.

श्री बालेश्वर राम : मैं कहना चाहता हूं कि आपके सवाल के जवाब में ही मैंने कहा था कि इसका जो महत्व है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हमने कभी नहीं कहा कि सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। हमने कहा कि हमारी कोशिश जारी है कि गरीबी को दूर कर सकें। जहां तक हमारे प्रयत्न हो सकते हैं हम लगे हुए हैं। हम कभी नहीं कहते सभी को मकान दे दिया, खाने को पूरा भोजन दे दिया, या पूरे साधन दे दिये। यह तो हमारा दावा नहीं है। हमारी कोशिश जरूर है। आपने हमारा ध्यान इस समस्या की तरफ दिलाया और शार्ट नोटिस में हमने पूरी कोशिश की राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करें। आप जानते हैं कि सब जगह राज्य सरकारें काम कर रही हैं। जहां भी कोई नेशनल कैलेसिटी होती है, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या अन्य किसी प्रकार की विपत्ति हो इसके लिये प्लानिंग कमीशन ने राज्य सरकारों को पैसा दिया है जिससे

**Not recorded.

[श्री बालेश्वर राम]

राज्य सरकारें इस काम को करती हैं। आपने इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया, हमने राज्य सरकारों को कहा है कि आइडेन्टिफाई कीजिये कहां-कहां लोग मरे हैं। उसके बाद अगर राज्य सरकारें कहेंगी कि इतने लोग मरे हैं तो फिर विचार किया जायेगा। यह भी सम्भव है कि आपके पास जो जानकारी हैं उससे अधिक जानकारी राज्य सरकारों से मिले, या जो आपकी जानकारी हो उसमें कुछ गलती हो। राज्य सरकारों के पास ऐसी विपदाओं से निपटने के लिये साधन हैं। और अगर उतने से काम नहीं चलता और वह हमसे कहेंगी तो हम पुनः विचार कर सकते हैं। लेकिन इस गम्भीर सवाल के साथ दूसरी बातों को कहना, जैसे इन्होंने एशियन गैम्स की बात कही, यह ठीक नहीं है। एशियन गैम्स की वजह से कम से कम मजदूरों को काम मिल रहा है, दिल्ली की सड़कें अच्छी हो रही हैं। इस बारे में विचारों का मतभेद हो सकता है। दूसरी समस्याओं को, जितने राजनीतिक सवाल हैं, सब को इसके साथ जोड़ दीजिये तब तो एक विवाद का प्रश्न बनता है। इसलिये मैं कहता हूँ कि इस बात की गम्भीरता को हम समझते हैं, हमने राज्य सरकार से सम्बन्ध स्थापित किये हैं, फिर भी निर्देश दे रहे हैं कि जहां-जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उनकी जो मदद हम कर सकते हैं, करनी चाहिये। जहां तक मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है, हम आपकी भावनाओं के साथ हैं।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Don't record anything.

*(Interruptions)***

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे जो पहला अहम सवाल है, वह गिनती का इसमें कोई महत्व नहीं रखता है। अब 5 के बजाय 10 मर जायें, 10 के बजाय 20 मर जायें, आज तो क्रिकेट के समान हो रहा है। जैसे क्रिकेट में चौआ, छक्का हो रहा है, उसी तरह इस मामले में भी हो रहा है। आज 4 मरे हैं, कल 6 मरे हैं इसी तरह से चौआ और छक्का चल रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुनियादी सवाल यह है कि लोग मर क्यों रहे हैं? और मरने वाले लोग हैं कौन?

क्या ठंडक इस देश मे ही है या ठंडक इस देश के बाहर दूसरे मुल्कों में भी है? क्या इस देश में ही गरमी है या इससे ज्यादा अरब मुल्कों में भी है? जहां 6, 6 महीने बरफ रहती है, वहां कभी लोगों के मरने का सवाल नहीं आता है जहां आग बरसती है, वहां से मरने की शिकायत नहीं आती है। दिल्ली में बहुत ठंडक है, लेकिन दिल्ली की अपेक्षा बिहार में ज्यादा लोग मरे हैं। दिल्ली की अपेक्षा बिहार में कम ठंडक है लेकिन अगर इसकी तह में आप जायेंगे तो मरने वाले गरीब हैं, भुखमरी से मरने वाले हैं। यह मरने वाले वही हरिजन आदिवासी पिछड़े समुदाय के लोग और दलित वर्ग के लोग हैं।

लू किस को मारती है? जिसके पेट में अन्न नहीं रहता है उसको मारती है। लू के दिनों में भर पेट पानी पीजिए तो लू नहीं लगेगी, लेकिन जिसके पेट में पानी भी नहीं रहेगा तो उसको लू मारेगी। ठंडक किस को मारती है? जिस के पेट में अन्न नहीं होता है।

**Not recorded.

सबसे ज्यादा बुनियादी सवाल यह उठता है कि इसके लिये सरकार क्या कर रही है? शुरू में जब आपत्ति उठाई गई तो श्री वाजपेयी जी और दूसरे साथियों ने कहा था कि इस मामले में कृषि राज्य मंत्री क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्याद अगर कुछ कह सकते हैं तो वह इतना ही कह सकते हैं कि हमने कंबल बांट दिये और इतना कुछ कर दिया, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। किसी गांव में कुंआ खुदवाना हो, हस्पताल बनवाना हो, गांव के लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना हो तो यह सरकार के अलग-अलग विभाग हैं। इस मामले में अगर एक व्यक्ति जवाब दे सकता है तो वह प्रधान मंत्री ही दे सकती हैं कि कैसे लोगों को भुखमरी से बचाया जाये ?

आपका रेडियो डिपार्टमैंट, ब्राडकास्टिंग डिपार्टमैंट हैं, वह सब चीजों की खबरें देता है, लेकिन वह यह खबर क्यों नहीं देता कि शीत-लहरी आने वाली है, घर से बाहर नहीं जाओ।

श्री मनीराम बागड़ी : घर ही न हो जिनके ?

श्री राम विलास पासवान : घर नहीं है, दिल्ली में रैन-बसेरे की योजना बनाई गई थी कि रैन-बसेरे के तहत लोगों को रहने की सुविधा देंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि दिल्ली में रैन-बसेरे की योजना का क्या हुआ ? पूरे देश में उसको लागू करना था ? (**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't record anything. (*Interruptions*)**

श्री राम विलास पासवान : मैं कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन आज देश की क्या हालत है ? देश पहुँच गया है कंगाली की स्थिति में। पहले संसार में तीन तरह के देश माने जाते थे : फर्स्ट वर्ल्ड, सैकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। आज फोर्थ वर्ल्ड और फिफ्थ वर्ल्ड भी हो गए हैं। चौथी दुनिया में तो गरीब देश हैं और पांचवीं दुनिया में भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका जैसे कंगाल मुल्क हैं। कंगाल देशों में भी जो लोग मर रहे हैं, वे अधिक कंगाल हैं।

गरीबी की रेखा की बात की जाती है। गरीबी की रेखा कहां खींची गई है ? जिन लोगों की आमदनी एक रुपये रोज से कम है, वे गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं। यह मेरे पास सरकार का जबाब है 10 दिसम्बर, 1980 का, जिसमें बताया गया है कि बिहार में, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने लोगों के मरने की बात कही है, 58.91 परसेंट अर्थात् 50 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आजदी के 34 बरस के बाद भी बिहार में 59 परसेंट लोग ऐसे हैं, जो दिन में एक रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। आज एक रुपया से एक प्याली चाय की भी नहीं मिल सकती है। इस स्थिति में लोग मरेंगे नहीं, तो और क्या होगा ? जहां-जहां भी लोग ठंडक या गर्मी से मरे हैं, वहां की हालत आप देख लीजिए। बगल में हरियाणा है। वहां से तो शिकायत नहीं आती हैं कि लोग ठंडक या लू से मरे हैं, क्योंकि वहां स्थिति थोड़ी अच्छी है। लेकिन जहां लोगों के पास कुछ है नहीं, वहां लोग मरेंगे।

इन मौतों की बुनियाद में गरीबी और भुखमरी हैं। इसलिए जब तक उसकी

**Not recorded.

[श्री राम विलास पासवान]

तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं भी होती रहेंगी। हममें से कई लोग एशियाई गेम्ज़ की बात को गुस्से से कहते हैं। हम आपोज़ीशन में हैं। सरकार की कमजोरी से फायदा उठाना हमारा फर्ज है। इसलिए इन लोगों को इस पर दुखी नहीं होना चाहिए। मैं इनके नेता की बात बताता हूं। जब नारायणपुर की घटना घटी, तो प्रधान मंत्री वहां गई थीं। वहां पर प्रैस वालों ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी का उस समय का वक्तव्य है कि मैं विरोध में हूँ, मैं पालिटीशन हूँ, हमारी संन्यासियों की जमात नहीं है, मेरा काम है सरकार की कमजोरी से फायदा उठाना। आज जब हम आपोजीशन में हैं, तो हमारा भी यह दायित्व है। इसमें हमारे दो परपज हैं : जहां हम सरकार की कमजोरी से फायदा उठाते हैं, वहां हम उसको यह चेतावनी भी देते हैं कि वह इस फ्रंट पर मजबूत हो। यदि सरकार काम करेगी, तो हमारे कहने से उसका कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। हमारे साथियों को इस पर दुख नहीं होना चाहिए।

सब से बड़ी बात है फिजूलखर्ची की। कौन आदमी नहीं चाहेगा कि फिजूलखर्ची को रोका जाये ? लेकिन सरकार के दृष्टि-कोण से वह फिजूलखर्ची नहीं है। वह एक अच्छी चीज़ है, जबकि हमारे दृष्टिकोण से वह फ़िजूलखर्ची है। लेकिन सवाल यह है कि प्रायर्टी किसको देनी चाहिए। प्रायर्टी इस बात को देनी चाहिए कि जो आदमी भूखा मर रहा है, ठंडक में जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसकी मदद की जाए। आज देश में क्या हो रहा है ? लोग धर्म-परिवर्तन आदि की बात करते हैं। उस सबकी तह में अधिकांश तौर पर गरीबी और भुखमरी निहित है। इस बुनियादी समस्या का निदान कैसे हो, प्रायर्टी किसको दी जाए, सब लोगों को बैठ कर इस पर सोचना चाहिए।

प्राथमिकता किस को दी जाए ? खेल-कूद को, या जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं हैं, उसको वस्त्र देने को, जिसके पेट में अन्न नहीं है, जिसके सिर पर झौंपड़ी भी नहीं हैं, उन्हें राहत देने को ? स्टेशन पर जहां फर्स्ट क्लास एयर-कंडीशन्ड के वेटिंग रूम हैं, वहीं प्लेटफार्म भी हैं, जहां गरीब लोग शीत लहर में भी बिना कपड़ों के सोए रहते हैं और ठिठुर कर मर जाते हैं। वहां पर पुलिस घूमती रहती है—मैं देहात की नहीं, शहर की बात कर रहा हूँ—, तो क्या यह पुलिस का फर्ज नहीं है कि जो व्यक्ति ठंडक में रात को प्लेटफार्म पर या सड़क पर सोया हो, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसका मां-बाप नहीं है, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं हैं, उसे उठा कर ऐसे स्थान पर पहुँचा दे, जहां वह ठिठुर कर न मरे ? यह प्रश्न तो मानवता के मूल्यों पर आधारित है। इस लिए इसको बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, सरकार इस तरह का कोई हाई पावर कमीशन बनाने जा रही है जो इसका पता लगावे कि ठंड से मरने वाले लोग या गर्मी से मरने वाले लोग कैसे मरते हैं और उनके लिए क्या उपचार किया जा सकता है, क्या व्यवस्था की जा सकती है ? इस तरह का कोई कमीशन क्या सरकार बनाएगी ?

दूसरे, सरकार के पास इस साल की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछले तीन साल की रिपोर्ट क्या सरकार बतलाएगी कि पिछले तीन सालों में कितने लोग ठण्ड के मारे मरे हैं, कितने लोग गर्मी के मारे मरे हैं ?

ठीक है अभी की रिपोर्ट मान लेते हैं कि नहीं है, अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरे पास तो रात को काल अटेंशन आया है, मैं क्या कर सकता हूं ? लेकिन क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि विगत तीन वर्षों में कितने लोग ठण्ड के मारे मरे हैं और कितने लोग लू के मारे मरे हैं ?

जो रैन बसेरा योजना के बारे में कहा गया कि गरीबों के लिए यह योजना चलायी जायगी और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में चलायी जायगी, उस रैन बसेरा योजना का क्या हुआ ?

यह जो रेडियो और ब्राडकास्टिंग का विभाग है क्या इसका यह दायित्व और फर्ज नहीं हो जाता है, कि लोगों को ऐसे समय में चेतावनी दे ? जिस तरह से कहीं अगर तूफान आने वाला होता है तो उसकी चेतावनी वह देता है कि तूफान आने वाला है, सचेत हो जाओ, ऐसे ही अगर भयंकर शीत-लहर चलने वाली हो तो क्या उस जगह के लोगों को वह यह नहीं बतला सकता है कि भयंकर शीत लहर आने वाली है, आप लोग अपने बचाव का उपाय करें ? ये सारी समस्याएं हैं जिसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय जवाब दें और इसको गम्भीरता से लें। मेरा सिर्फ यही कहना नहीं है कि आप केवल कृषि मन्त्री हैं, कृषि मन्त्री होने के नाते आप सरकार के एक अंग हैं। आप जहां बैठते हैं, वहां सरकार को बतलाइए, अपने सुपीरियर मन्त्री को बतलाइए और कैबिनेट में बैठ कर जहां से पालिसी तय होती है वहां से कोई ठोस कदम उठाइए, तब इस समस्या का निदान होगा। नहीं तो कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे, उससे कोई समस्या का निदान होने वाला नहीं है।

श्री बालेश्वर राम : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बातें आम तौर पर फिर वही कही गई हैं जो बागड़ी जी ने शुरू की थीं। करीब-करीब वही बातें आई हैं और जब कहना है तो बातें तो वही रहेंगी। मैंने तो कहा शुरू में कि इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि हिन्दुस्तान की गरीबी को हम नहीं मिटा सके हैं और हिन्दुस्तान में अभी भी करीब-करीब 48 प्रतिशत, जो औसत आंकड़े हैं, उनके हिसाब से लोग बिलो पावर्टी में रहते हैं। इससे भी हम इन्कार नहीं करते कि लोगों के पास घर नहीं हैं पूरे जोकि होने चाहिएं। बेसिक नेसेसिटीज जो चाहिएं, वह हम पूरी तरह से सब को नहीं मुहैया कर पाये हैं। हमारा प्रयत्न जरूर है।

जिस तरह आपने चर्चा की, यह बात सही है कि हमने कई कार्यक्रम भी शुरू किए, अब कहां तक उसमें सफलता मिली है उस का लेखा-जोखा करने की आवश्यकता है। यह बात नहीं है कि गरीबी दूर करने की तरफ हमारा प्रयास नहीं है। मैं सिर्फ एक दो उदाहरण उसके देना चाहता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ इसी को देख कर कि हमारे बहुत से लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, एक बड़े पैमाने पर हम चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलें और उसके लिए करीब-करीब 15 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान हमने इस छठी योजना में सेंट्रल और स्टेट सेक्टर में किया है और बैंकों से तथा जो इंस्टीच्यूशनल फाइनेंस हैं उससे भी उम्मीद करते हैं कि 3 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया वह गरीबों के लिए देंगे। उद्देश्य भी हमारा यही है कि पूअरेस्ट एमंग्स्ट द पूअर इससे लाभान्वित हों। इसलिए हमने जो गाइड लाइन्स राज्य-सरकारों को दी हैं उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग इससे

[श्री बालेश्वर राम]

लाभान्वित हो सकें। इसी तरह हमारी एन. आर. ई. पी. की जो स्कीम है उसमें भी अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें यह हमारा प्रयास है। और भी कई तरह के प्रोग्राम हम चला रहे हैं, मैंने शुरू में कहा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। हमारा कभी दावा नहीं रहा कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। लेकिन हमने प्रयास जरूर शुरू किया है। हम कर भी रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप का भी सहयोग पूरी तरह से हमें मिले तो इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं।

आपने रेडियो की चर्चा की। रेडियो से इसका प्रसारण करते हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि पांच डिग्री से नीचे जब मरकरी ड्राप करता है तो उस के बाद वह कहते हैं कि शीत लहर चलेगी। छः डिग्री से नीचे का अभी तक का उनका अनुमान है। मैंने मीटरियोलाजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया था और उनसे मैंने यह सवाल किया था, यद्यपि आप मेरी राय से सहमत होंगे कि इस में ऐसे ही लोग मरते होंगे जिनके पास कि घर नहीं होता, वह बेचारे कहीं पेवमेंट पर सोते हैं या वैगर्स हैं, भिखारी हैं, वह रेडियो कहां सुनने वाले हैं, उनको रेडियो कहां मिलता है? लेकिन फिर भी मेट्रियोलाजिकल डिपार्टमेंट से पूछा कि आपको चेतावनी देनी चाहिए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे मरकरी आती है तब उसको हम शीत लहर मानते हैं और उसको पूरी तरह से एक चेतावनी के रूप में प्रसारित करते हैं। इस प्रकार की मौसम सम्बन्धी सूचनायें रोज ही रेडियो से प्रसारित होती रहती हैं। लेकिन अभी तक उनके माप-दण्ड के अनुसार शीत लहर नहीं आई है।

13 hrs.

श्री मनीराम बागड़ी : फिर कैसे मर गए?

श्री बालेश्वर राम : थोड़ी सी ठण्ड में भी कोई आदमी मर सकता है। कोल्ड-वेव न भी हो लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा न हो तो थोड़ी सी ठण्ड में भी वह मर सकता है। अभी मैं, कोल्ड-वेव का जो माप-दण्ड उन्होंने रखा है, वह बता रहा था। हो सकता है कि उसको रिवाइज करने की जरूरत हो कि अमुक डिग्री पर ही चेतावनी दी जाया करे। मैंने आपका यह सुझाव नोट कर लिया है।

बाकी जो अन्य जनरल बातें हैं उनसे मैं इन्कार नहीं करता। हम और आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है। लेकिन आप इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न न करें।

श्री राम विलास पासवान : रैन-बसेरा और कमीशन एप्वाइन्ट करने के बारे में मैंने पूछा था।

श्री बालेश्वर राम : कमीशन बहाल करने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उस पर जो खर्चा आयेगा उससे गरीबों में कम्बल बांटना अच्छा रहेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : अंग्रेजों के जमाने में जो फेमीन कोड था उसको रिवाइज किया गया है लेकिन शीत लहर का जो पैमाना अंग्रेजों के जमाने में चल रहा था वही आज भी चल रहा है। इसलिए क्या इस पैमाने को रिवाइज करने के लिए आप कोई कमीशन मुकर्रर करेंगे?

श्री बालेश्वर राम : कमीशन मुकर्रर करने से कोई फायदा नहीं होगा । यह शीत लहर या हीट-वेव जो चलती है, आपने सुना होगा दो साल पहले इंग्लैण्ड में हीट-वेव चली थी जिसमें कई लोग मर गए थे । इसी प्रकार से अगर शीत लहर न भी हो, कम ठण्ड में भी लोग मर सकते हैं । बहरहाल यह जो समस्यायें हैं इनके समाधान में आपको हमारा हाथ बटाना चाहिए । इस समस्या की ओर हम पूरी तरह से जागरूक हैं ।

PETITION *RE* INCENTIVES AND FACILITIES TO SCIENTIFIC/ ELECTRONIC INSTRUMENTS EXPORTERS IN AMBALA CANT.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): I beg to present a petition signed by Shri Anil Jain and others regarding incentives and facilities to scientific/ electronic instruments exporters in Ambala Cantt.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 14.05 hrs.

13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till five minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at eleven minutes past fourteen of the Clock.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) ; With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 21st December, 1981, will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:

   (a) The Plantation Labour (Amendment) Bill, 1981.

   (b) The Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Amendment Bill, 1981.

   (c) The Pharmacy (Amendment) Bill, 1981.

3. Consideration and passing of the Aligarh Muslim University (Third Amendment) Bill, 1980.

4. Discussion on the Sixth Five Year Plan on a motion to be moved by the Minister of Planning ;

5. Discussion on the Motion for modification of Maruti Limited. (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1981, given notice of by Sarvashri N. K. Shejwalker and Satish Agarwal on Tuesday, the 22nd December, 1981.

6. Discussion on the Motion for annulment of All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1981, given notice of by Sarvshri N. K. Shejwalkar and Phool Chand Verma on Wednesday, the 23rd December, 1981.

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara): I suggest that the following items may be included in the next's business Steps for a permanent